ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

लाजवाब औषधीय फूल है गेंदा

रविवारीय, 24-30 नवंबर 2019, वर्ष- एक, अंक-16, रांची | हिन्दी साप्ताहिक | R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 | कुल पृष्ठ 4 | मूल्य 2 रूपये

झारखंड राज्य में पर्यावरण, प्रदूषण, कृषि, ग्रामीण विकास एवं सामाजिक विषयों पर डॉक्युमेंट्री बनाने के लिये संपर्क करें

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

रेलवे की पेंशन अदालत 16 दिसंबर को हटिया में

रांची : रांची मण्डल रेल प्रबन्धक कार्यालय, हटिया के मण्डल सभागार में दिनांक 16.12.2019 (सोमवार)को 11.00 बजे पेंशन अदालत बैठेगी। रांची मण्डल से सेवानिवृत या मृत कर्मचारी के आश्रित पेंशनर / फॅमिली पेंशनर अपना आवेदन मण्डल कार्मिक अधिकारी, रांची के सेट्लमेंट सेक्शन में आवेदन निर्धारित प्रोफ़ार्मा में भर कर मांगा गया है। सभी आवेदन 02/12/2019 तक मण्डल कार्मिक के कार्यालय में जमा हो जाना चाहिए। इसके बाद पहुंचने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। पेंशन अदालत का उदेश्य रेल कर्मियों के पेंशन / फॅमिली पेंशन से जुड़े विवादों का रेल नियमों के तहत त्वरित निपटारा करना है। पहले हल हो चुके केस की फिर सुनवाई नहीं होगी। पेंशन अदालत के आवेदन के प्रारूप को कार्मिक विभाग के वेबसाइट www.ser.indianrailways.gov.in <http://www.ser.indianrailways.gov.in> से डाउनलोड किया जा सकता है। सभी से अनुरोध किया जाता है कि यथाशीघ्र अपने आवेदन जमा करवा दें।

एकल उपयोग वाली प्लास्टिक की कई ऐसी वस्तुयें हैं जिनका विकल्प खोजना है आवश्यक

क्या बंद हो पायेगा एकल प्लास्टिक?

वरीय संवाददाता

रांची : प्लास्टिक की वैसी वस्तुएं जिनका हम एक बार उपयोग कर के उसे फेंक देते हैं उन्हें एकल प्लास्टिक कहते हैं। पतले कैरी बैग , पलास्टिक के ग्लास, कप प्लेट इसी श्रेणी में आते हैं। सरकार ने इन पर रोक के प्रयास किये हैं लेकिन इन प्रयासों पर पानी फिर सकता है ?भले माइक्रो प्लास्टिक से बने कैरी बैग अब नहीं दिखते, पर कई ऐसे प्लास्टिक से बनी वस्तुएं हैं जो आज भी हम धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं और उनका कोई उपचार नहीं होता या उन्हें रिसाइकल भी नहीं किया जाता। अभी शादी विवाह के समय में तकरीबन प्रत्येक पार्टियों में पानी पीने के लिये प्लास्टिक के ग्लासों का ही उपयोग होता है। ऐसे हजारो ग्लासों को अंततः कचड़े में ही फेका जाता है। ये ग्लास मोटे प्लास्टिक के बने होते हैं और इनके प्राकृतिक रूप से नष्ट होने की कोई संभावना नहीं होती। यही हाल प्लास्टिक से बने कप प्लेटों का भी होता है। कम गुणवत्ता वाला प्लास्टिक पर्यावरण में जस का तस बना रहता है। यानी इसे रिसाइकिल नहीं किया जा सकता है। यही सबसे बड़ी मुश्किल है। 'बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन' थीम के तहत संयुक्त राष्ट्र ने नारा दिया है। उसका कहना है, 'अगर आप प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, रिसाइकिल नहीं कर सकते हैं, तो उसे इस्तेमाल न करें। लेकिन कई मौकों पर कोई विकल्प न होने से भारत मे यह संभव नहीं लगता।

झिझक और उपहास आड़े आता है

पार्टियों में पानी पीने के लिये उपयोग होने वाले प्लास्टिक ग्लासों का शहरों में कोई विकल्प भी नहीं दिखता। पहले गांवों में कुम्हार के यहां से मिट्टी के ग्लास पानी पीने के लिये मंगाये जाते थे। जो उपयोग के बाद फेंक दिये जाते थे इनसे कोई नुकसान भी नहीं था। इससे कुम्हारों को भी रोजगार प्राप्त होता था। अब ये विकल्प शहरों में संभव नहीं। भले चाय की चुस्कियों के लिये लोगों की पसंद कुल्हड़ वाली चाय है लेकिन पार्टियों में लोग कुल्हड़ में पानी पीना पसंद नहीं करेंगे? प्लास्टिक के कप प्लेट रिसाइकल नहीं होता और उपयोग होने के बाद हजारो की संख्या में ये कचड़े के रूप में एकत्र हो जाते हैं। भले इन्हें उठा कर कहीं डंप कर दिया जाये पर ये नष्ट होने वाले पदार्थ नहीं हैं। ऐसे में प्लास्टिक से होने वाले नुकसान को जानने के बाद भी पार्टियों में पत्तों से बने दोने और पत्तलों के उपयोग में आम शहरी को अभी भी झिझक है। लालू यादव ने रेल मंत्री रहते मिट्टी के कुल्हड़ में चाय बिकवाई तो उसका भी उपहास उड़ाया गया।

शराब पीने वालों पर दोहरी मार

शराब पीने वाले ज्यादतर लोग बाहर कहीं भी इन प्लास्टिक ग्लासों में ही शराब का सेवन करते हैं। शराब का एल्कोहल इन प्लास्टिक ग्लासों के एक पतले परत को घुला देता है। इस तरह शराब पीने वालों को दोहरा नुकसान होता है। शराब के नुकसान के अलावा उसमें घुली हुई यह प्लास्टिक कैंसरकारक होती है। यही हाल थर्मोकोल और पेपर से बने कप प्लेटों का भी है।थर्मोकोल बनाने में कई ऐसे ठोस उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, जो पानी में घुलनशील नहीं होते। इसके अलावा इसे बनाने में इसमें मिलाए जाने वाले तेल, ग्रीस, सल्फाइट और अन्य कई रासायनिक उत्पादों जैसे लेड, मरकरी, आयरन और एल्युमिनियम तक का इस्तेमाल किया जाता है। पेपर कप में गर्म चाय डालने से उसकी एक परत घुल कर चाय के साथ मिल जाती है जो स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है। दरअसल पेपर से बने कपों में भी प्लास्टिक की कुछ मात्रा होती है।

सख्ती का असर भी दिखा है

प्लास्टिक कैरी बैग फिलहाल बाजार से गायब हैं और कुछेक दूकानदार ही चोरी छिपे इसमें सामान बेच रहे हैं। इसके पीछे भी आम लोगों और ग्राहकों की ही लापरवाही है। अगर लोग घर से बैग या झोला लेकर जायें तो दूकानदारों को कैरी बैग चोरी छूपे भी रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी, पर इसकी आदत लोगों को डालनी पड़ेगी। दूसरी और पर्यावरणविदों का कहना है कि मैन्यूफैक्चरर्स को कोई लाइसेंस या पेटेंट तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक वह इस बात का खुलासा न करें कि वे इन उत्पादों को कैसे प्रोसेस करेंगे? जो प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं हो सकती है, उस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।

पक्षियों के मौत के बाद अब ड्रामा

●एवियन बोट्यूलिज्म से हुई है सांभर झील में 18 हजार पक्षियों की मौत

●झील के गहरे पानी वाला इलाके में अभी भी कई मृत पक्षी तैर रहे हैं।

एजेंसियां :राजस्थान की सांभर झील में पक्षियों की मौत के बीच विभागीय लापरवाहियों के कई और सच सामने आए हैं। पक्षियों को बचाने की बजाय पशुपालन विभाग और वन विभाग अपनी जिम्मेदारी और भार एक-दूसरे पर डाल रहे हैं। दोनों विभागों के बीच सामंजस्य की बेहद कमी है। क्योंकि सांभर झील का एरिया दोनों विभागों से संबंधित नहीं है। साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि 10 नवंबर को मीडिया में मामला आने से काफी पहले स्थानीय लोगों और पक्षी प्रेमियों ने सरकारी एजेंसियों को पक्षियों की मौत के बारे में बताया दिया था, लेकिन विभागों ने समय रहते कोई कदम नहीं उठाया।

मामले में 13 नवंबर को स्वतः संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने वकील वकील नितिन जैन को न्याय मित्र नियुक्त किया था। जैन ने कोर्ट में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट में लिखा है कि जिस तरह से अभी रेस्क्यू का काम चल रहा है, उस हिसाब से मृत पक्षियों को बाहर निकालने में एक- दो महीने का वक्त और लग जाएगा। इस तरह की सुस्ती आपदा की स्थिति को और बड़ा कर सकती है।10 पेज की इस रिपोर्ट में प्रशासन की बचाव कार्य और पक्षियों के बचाव कार्य से संबंधित कई खामियों को उजागर किया गया है। झील के गहरे पानी वाला इलाके में अभी भी कई मृत पक्षी तैर रहे हैं। रिपोर्ट में पक्षियों के रेस्क्यू करने पर भी सवाल उठाए गए हैं। इसके मुताबिक जिन पक्षियों को रेस्क्यू किया गया उन्हें तुरंत रेस्क्यू सेंटर नहीं ले जाया गया। घायल पक्षियों को एक खुले कार्डबॉक्स में कई घंटों तक रखा गया। एक रेस्क्यू सेंटर है जो झील से करीब 15 किमी दूर है। न्यायमित्र के अनुसार सांभर सॉल्ट लिमिटेड के अधिकारियों ने भी सरकारी एजेंसियों को सूचित करने में गंभीरता नहीं दिखाई जबकि इनके पास पूरी झील में जाने के लिए ट्रेन भी है। कंपनी ने झील के कई हिस्से निजी नमक उत्पादकों को लीज पर दे रखे हैं। ये उत्पादक झील में जहरीला कचरा झील में डाल रहे हैं। तथ्यात्मक रिपोर्ट में स्पष्ट कहा गया कि बचाव कार्य के लिए लोगों की कमी है। अगर जल्द ही पक्षियों की लाशें नहीं हटाई गईं तो झील में मौजूद लाखों देशी-विदेशी पक्षी भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। लेकिन मृत पक्षियों को गहरे पानी से बाहर लाने के लिए सरकारी एजेंसियों के पास कोई सुविधा नहीं है। हैरान करने वाली बात है कि सरकारी एजेंसियां हवा की दिशा बदलने का इंतजार कर रही हैं ताकि मृत पक्षी किनारे पर आ सकें और उन्हें इकट्ठा किया जा सके।

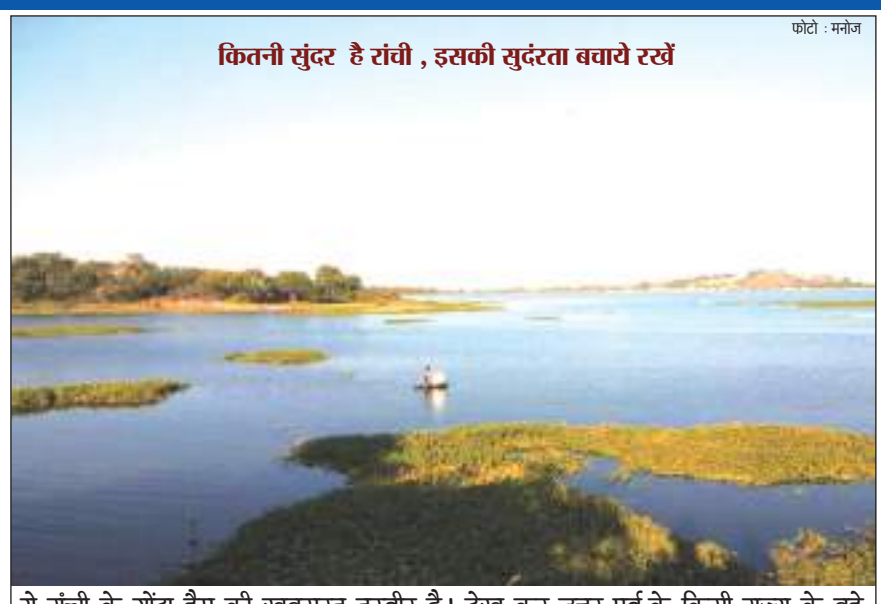

फोटो : मनोज

कितनी सुंदर है रांची , इसकी सुदंरता बचाये रखें

ये रांची के गोंदा डैम की खुबसूरत तस्वीर है। देख कर उत्तर पूर्व के किसी राज्य के बड़े झील का अहसास होता है। मॉनसून के आखिरी दिनों में हुई घनघोर बारिश से डैम में पर्याप्त पानी एकत्र हो गया है। मछुआरे ट्यूब और डब्बों से बने अपनी नाव से इसमें मछली मारते हैं। अगर इसमें से जलकुंभी निकाल दिया जाये तो यह स्वच्छ हो जायेगा। जलकुंभी और प्रदूषण के कारण ही ऑक्सीजन की कमी से पिछले साल यहां हजारो मछलियां मर गयी थीं।

बीएयू में सेंटर फॉर एडवांस्ड हायर एजुकेशन (कास्ट) प्रोजेक्ट का प्रीलांच

संवाददाता

●**राज्य के सभी जिलों के लिए उपयुक्त समेकित कृषि प्रणाली विकसित करने को प्राथमिकता : कुलपति**

●**कास्ट प्रोजेक्ट लांच होने वाला बीएयू देश का इकलौता विश्वविद्यालय**

रांची : बीते शुक्रवार को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में समेकित कृषि प्रणाली आधारित सेंटर फॉर एडवांस्ड हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट (कास्ट) का प्रीलांच सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय समन्वयक (कास्ट प्रोजेक्ट) डॉ पीके घोष ने कहा कि पूरे विश्व की यह पहली परियोजना है, जिसमें उच्च शिक्षा के संवर्धन को विश्व बैंक ने प्रायोजित किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण कृषि शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस परियोजना के हितकारक स्नातकोत्तर छात्र, शिक्षक, वैज्ञानिक एवं किसान होंगे. इसके अंतर्गत छात्रों एवं शिक्षकों को देश-विदेश के नामी संस्थाओं में भेजा जायेगा।

इस परियोजना के छात्र, किसान,शिक्षक और वैज्ञानिक प्रमुख हितधारक होंगे।

डॉ. घोष ने बताया कि झारखंड राज्य में विकास की गतिविधियों को गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण और बीमार स्वास्थ्य की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। परियोजना में समेकित कृषि मॉडल से ग्रामीण स्तर पर बेहतर आजीविका और सामाजिक आर्थिक उत्थान के संदर्भ में चुनौतियों को कम करने में सहायता मिलेगी।

परियोजना से सभी जिलों के लिए उपयुक्त समेकित कृषि प्रणाली विकसित होगी: कुलपति

कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. आरएस कुरील ने कहा कि बीएयू देश का इकलौता विश्वविद्यालय है, जहाँ 23 करोड की लागत की लागत से सेंटर फॉर एडवांस्ड हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट (कास्ट) परियोजना की स्वीकृति मिली है। इस महत्वकांक्षी परियोजना की स्वीकृति देकर आईसीएआर ने बीएयू की गरिमा बढा दी है। यह परियोजना आईसीएआर की राष्ट्रीय उच्च कृषि शिक्षा के तहत विश्व बैंक से प्रायोजित है।

कुलपति डॉ. आरएस कुरील ने बताया कि परियोजना के अधीन झारखण्ड राज्य के सभी जिलों में समेकित कृषि प्रणाली का प्रमाणीकरण किया जायेगा। राज्य के सभी 24 जिलों में प्रत्येक जिले के स्थानीय पारिस्थिकी के अनुरूप एक-एक समेकित कृषि मॉडल को विकसित किया जायेगा। इस मॉडल में कृषि के साथ कृषि वानिकी, कुक्कुट, बकरी, सूकर, मधु मक्खी पालन आदि अवयवों को शामिल किया जायेगा। उन्होंने कहा की राज्य में 10-15 लाख टन खाद्यान उत्पादन की कमी है। इसके कार्यक्रमों से फसल विभव और फसल उत्पादकता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। राज्य में करीब 14 प्रतिशत सिंचाई की सुविधा है, इसके शोध कार्यक्रमों से सिंचाई के अन्य साधनों को विकसित करने में मदद मिलेगी. योजना में किसानों की आय दुगुनी करने के नवीन तकनीकों पर भी शोध कार्य होगा।

कुलपति ने कहा कि इस योजना में कृषि अनुसंधान से जुड़े 30 स्नातकोत्तर तथा 20 पीएचडी छात्र छात्राओं को गुणवत्तापुर्ण अनुसंधान कराया जायेगा। 8 अंतर्राष्ट्रीय एवं 30 राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होगा। 30 वैज्ञानिकों को कृषि एवं संबद्ध विषयों में दुनिया के विकसित देशों में चीन, यूनाइटेड किंगडम। युएसए, इजराईल फ़िलीपीन्स,

.....शेष पेज 3 पर

माननीयों को प्रदूषण से कोई लेना देना नहीं

दिल्ली में पराली का धुंआ हो या झारखंड में प्रदूषण या कटते पेड़ इन सभी पर राजनीतिक दल एक दूसरे को नीचा दिखाने में तो आगे रहते हैं, पर संसद में प्रदूषण पर चर्चा में महज 18 प्रतिशत सांसद ही उपस्थित रहे।

हाल ही में चुनावी सरगर्मी के बीच दो खबरें चर्चा नहीं पा सकीं। पहली बरही में सड़क चौड़ीकरण में तकरीबन 12 हजार पेड़ काटे गये उनमें से आधे पेड़ों की शिफ्टिंग होनी थी जो नहीं हुई। और जमशेदपुर में एक महिला ने सीएम के आवास के सामने एयरपोर्ट के लिये हजारो पेड़ों के काटने के विरोध में प्रदर्शन किया।

दिल्ली के प्रदूषण पर कुछ दिन पहले ही चर्चा में भाग नहीं लेने पर भाजपा सांसद व पूर्व भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर की काफी आलोचना हुई थी। मगर अन्य सांसदों को भी दिल्ली के घुटते दम को लेकर कोई चिंता नहीं है। इसका नजारा लोकसभा में भी दिखा जब प्रदूषण जैसे गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी।

शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को लोकसभा में प्रदूषण पर गंभीर चर्चा आयोजित की गई। मगर खाली पड़ी सीटों के बीच महज कुछ सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। उनमें से भी कुछ तो इस दौरान बस सियासी हमले ही करते रहे। दिल्ली में रहने वाले लोगों की सेहत की चिंता को लेकर हमारे माननीय कितने गंभीर हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मंगलवार को महज 18 फीसदी उपस्थिति ही रही। दिल्ली में भाजपा के सात सांसद हैं, लेकिन इनमें से रमेश बिधूड़ी और हंसराज हंस ने चर्चा में हिस्सा ही नहीं लिया। सवाल सिर्फ सांसदों पर ही नहीं, लोकसभा के अधिकारियों और स्टाफ पर भी उठ रहा है जो इस दिन सदन पहुंचे ही नहीं। लोकसभा स्पीकर ने इस पर भारी नाराजगी जताते हुए इन्हें नोटिस जारी किया है।

आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति

प्रदूषण पर चर्चा के दौरान दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा आरोप-प्रत्यारोप की राजनीति में ही उलझे रहे। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने आप सांसद भगवंत मान भी संसद नहीं पहुंचे। हालांकि, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने गंभीरता से प्रदूषण का मुद्दा उठाया। उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि दिल्ली में किस तरह प्रदूषण का आतंक मचा हुआ है।

प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट तक अपनी चिंता जाहिर कर चुका है। राज्य सरकारों और अफसरों को भी उसने फटकार लगाई है। उसके सख्त निर्देश पर ही पंजाब-हरियाणा जैसे राज्यों में पराली का जलाना कम हुआ है। अन्यथा राजनीतिक दलों में सियासी खेल ही चलता रहा था। कोई भी दल किसानों को नाराज करने के डर से कदम नहीं उठाना चाहता था। हां, सियासी बयानबाजी खूब हुई।

गौतम गंभीर का मामला शायद ही कोई भूला होगा जिसमें वह इसी मुद्दे पर निशाने पर आ गए थे। प्रदूषण को लेकर होने वाली एक महत्वपूर्ण बैठक के दिन वह दिल्ली में ही नहीं थे, बल्कि भारत-बांग्लादेश टेस्ट के दौरान कमेंट्री के लिए इंदौर पहुंच गए। यहां उनका जलेबी खाता फोटो वायरल हो गया। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने उनपर हमला बोल दिया। गंभीर ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उनके जलेबी खाने से प्रदूषण रुकता है तो वह जलेबी खाना छोड़ देंगे। इसे लेकर राजनीति अब भी जारी है। बहरहाल, आज हुई चर्चा के दौरान वह संसद में जरूर मौजूद थे और उन्होंने अपनी बात भी रखी।

जब प्रदूषण पर देश और दिल्ली में हाहाकार मचा हो ऐसे में हमारे माननीयों की संसद में गैरमौजूदगी और उनका रवैया चौंकाता जरूर है। जब हमारे सांसद ही कुछ बोलने और सुनने को तैयार नहीं हैं तो इससे लड़ने का एक मजबूत खाका तैयार होने की बात ही दूर की कौड़ी नजर आती है। सांसदों ने आज बता दिया कि दिल्ली की जनता को अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। पराली जलाने पर दिल्ली की धुंध और उसके बाद आरोप प्रत्यारोप देख वह या तो वह रामभरोसे रहे या फिर सुप्रीम कोर्ट के भरोसे।

प्रदूषण का व्यावसायिक दोहन

कुछ दिनों पहले टीवी चैनलों में एंकर और डॉक्टर ये बता रहे थे कि, प्रदूषित दिल्ली में आप कैसा मास्क पहनें? अगर प्रदूषण स्तर कम है तो फलां मास्क और ज्यादा है तो फलां मास्क पहनें। चुंकी न्यूज चैनलों को कुछ न कुछ दिखाते रहना होता है इसलिये वो ये सब कर रहे थे। कार्यक्रम में कोई डॉक्टर भी आये हुये थे जो कई प्रकार के मास्क को दिखा कर उसकी बनावट और उसके फायदे बता रहे थे। मास्क किस प्रकार से आप को बचायेगा ये जानकारी भी दे रहे थे।

गौर से सोचें तो हमें यह एक दुखद प्रहसन सा लगेगा। क्या यह प्रदूषण कुछ के लिये व्यवसाय बन गया है? और हम बजाय प्रकृति को साफ सुथरा रखने के अब ये आदत बना लेंगे कि बहुत सारे उपकरण खरीद लें जिससे प्रदूषित हवा, पानी , भोजन से बच सकें? कई जानकारों का मानना है कि वाटर प्यूरीफायर अंततः हमारे लिये नुकसानदेह साबित होते हैं, यह पानी के मिनरल्स को भी फिल्टर कर निकाल देते हैं जिससे शरीर में कई तरह की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। और शरीर ऐसे पानी का आदी भी हो जाता है, घरों में लगाया जाने वाला एयर प्यूरीफायर मशीन एक भ्रम भी हो सकता है, और ये मामूली तौर पर हवा को शुद्ध करता हो? अब तो कुछ ही दिनों में ऐसे आवास बिकेंगे जिसमें ये विज्ञापन दिया जायेगा कि फ्लैटों में एयर प्यूरीफायर लगा कर बिक्री की जायेगी। ये महंगे उपकरण और और वाटर फिल्टर, एयर प्यूरीफायर, ऑक्सीजन कैफे, बैक्ट्रिया मारने वाले उपकरण किसी प्रकार के निदान नहीं है बल्कि हमें और लापरवाह और प्रमादी बनाने के इंतजाम हैं। इनका एक बाजार तैयार भी हो चुका है। जापान और कई यूरोपीय देशों में सड़कों के किनारे ऑक्सीजन चैंबर बने हुये हैं जिसमें प्रत्येक कुछ घंटे तक ट्रैफिक पुलिस कर्मी ड्यूटी कर-के जा बैठता है ताकी वाहनों के धुंओं से भरे उसके फेफड़ों को शुद्ध हवा प्राप्त हो सके, चीन ने अपने एक महानगर में विशाल एयर प्यूरीफायर टावर बना दिया है जो शहर के प्रदूषित हवा को शुद्ध करता है, लेकिन भारत में मास्क बेचने, हवा का कैफे खोलने और घरों में लगाने के लिये एयर प्यूरीफायर, वाटर प्यूरीफायर का बाजार बन रहा है। हम जंगलों तालाबों नदियों को बचाने वायु प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर लगाम लगाने के लिये गंभीर नहीं है, पर प्रदूषित हवा, पानी से बचाने वाले उपकरणों के बाजार का शिकार आज नहीं तो कल जरूर बनेंगे।

अमूमन हम प्रदूषण रोकने में तो कभी आगे नहीं रहते है लेकिन प्रदूषित हवा से, भोजन से, पानी से बचाव के लिये उपकरणों पर लाखो रुपये फूंक डालते हैं। हमारी ये फितरत कितनी हास्यास्पद है? दिल्ली में प्रदूषण रोकने पर कोई काम नहीं हुआ सिर्फ राजनीति हुयी लेकिन दिल्ली में हर तरह के वायु प्रदूषण से रोकने वाले मास्क और 500 रुपये में 15 मिनट शुद्ध खुशबूदार ऑक्सीजन सुंघाने वाले कैफे जरूर खुल गये हैं। एयर प्यूरीफायर का विज्ञापन नायिकायें कर रही हैं, लेकिन हम अपने आस पास पेड़ नही लगायेंगे, तालाबों नदियों को प्रदूषित करेंगे, और फिर हजारो रुपये का वाटर प्यूरीफायर और एयरप्यूरीफायर खरीद लेंगे।

गौतम गंभीर, काकोली दास चर्चा में

हाल ही में जिलेबी खाते दिखने पर लोगों ने गौतम गंभीर को ट्रोल करना शुरू कर दिया था। लोगों का कहना था कि दिल्ली में भयंकर प्रदूषण है और गंभीर बाहर जाकर जलेबी खा रहे हैं? गंभीर ने भी चिढ कर कह दिया कि मेरे जिलेबी न खाने से अगर प्रदूषण कम होता है तो मैं जिलेबी खाना छोड़ दूंगा। संसद में भी गौतम गंभीर ने अपनी बात रखी। गौतम गंभीर ने कहा कि यहां एक ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जो जाति, धर्म, आयु से परे है। ये हमें तब भी प्रभावित कर रहा है जब हम संसद में इसपर बात कर रहे हैं। हमें इस पर राजनीति बंद कर देनी चाहिए। ये स्थिति जलवायु आपातकाल की तरह है। दिल्ली सबसे ज्यादा प्रभावित है। ऑड-ईवन और निर्माण कार्यों पर रोक जैसे कदमों से इसपर काबू नहीं पाया जा सकता है। हमें लंबे समय तक चलने वाली ठोस योजना तैयार करनी होगी और आरोप-प्रत्यारोप का खेल बंद करना होगा। ये जिम्मेदारी के साथ काम करने का समय है। वहीं

संसद के शीतकालीन सत्र में मंगलवार को लोकसभा में टीएमसी सांसद डॉ. काकोली घोष दास्तीदार मास्क पहनकर प्रदूषण पर चर्चा करने के लिए पहुंची। कुछ लोगों के आपत्ति के बाद उन्होंने मास्क हटा दिया। तृणमूल सांसद ने कहा, 'जब हमारे पास 'स्वच्छ भारत मिशन' है, तो क्या हमारे पास 'स्वच्छ हवा मिशन' नहीं हो सकता है? क्या हमें स्वच्छ हवा में सांस लेने का अधिकार सुनिश्चित नहीं किया जाना चाहिए?उन्होंने कहा कि दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से 9 भारत में हैं। भारत दौरे पर आए एक प्रधानमंत्री ने प्रदूषण को लेकर प्रतिकूल टिप्पणी की, जो काफी हतोत्साहित करने वाला है। हमें एक-दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय मिलकर समस्या का हल खोजना चाहिए। यह हमारे देश, बच्चों और भविष्य का सवाल है। काकोली घोष दस्तीदार ने कहा कि प्रदूषण बढ़ने के कई कारणों में से एक कारण लोगों का अशिक्षित होना भी है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता कि उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। इसके बाद वे पराली जलाते हैं।

क्या फिर प्रलय होगा और लुप्त होंगे महाद्वीप!

डॉ. नितिश प्रियदर्शी

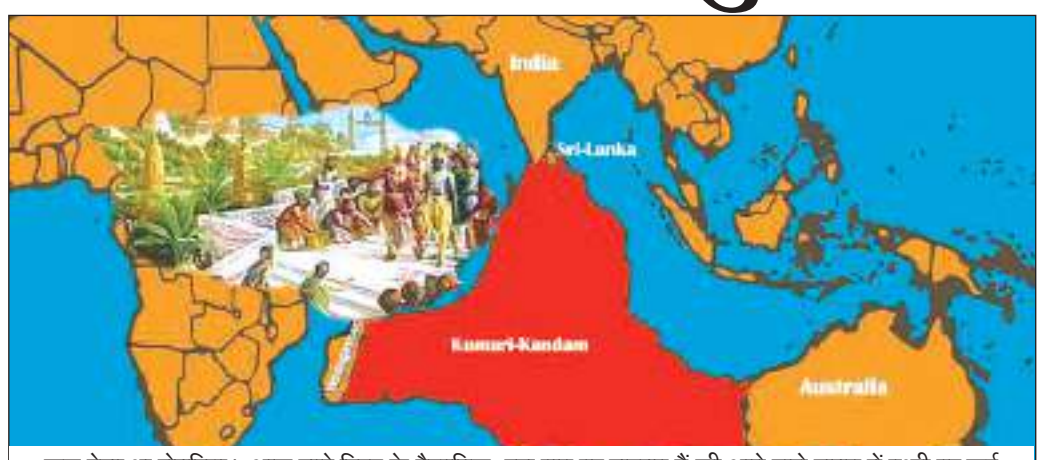

कुछ ऐसा था लेमुरिया। आज सारे विश्व के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं की आने वाले समय में पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होंगे। कारण है ग्लोबल वार्मिंग। कई छोटे द्वीप समुद्र में समा जायंगे । कहीं सूखे की मार होगी तो कहीं अतिवृष्टि। कई नए जगह भूकंप प्रभावित होंगे जो पहले नही थे । यानि विनाश का एक नया रूप सामने आएगा।

जिस तरह वर्तमान में ग्लोबल वॉर्मिंग के कारण पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होने की आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसी तरह प्राचीनकाल में एक बार ऐसा हो चुका है जिसके चलते लेमुरिया और मु नाम के दो महाद्वीप जलमग्न हो चुके थे। हालांकि वैज्ञानिक इस पर अभी शोध ही कर रहे हैं किंतु विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है कि इन दोनों महाद्वीपों पर सभ्यता काफी विकसित थी। कुछ खोजकर्ताओं, जिनमें फिलीप स्कोल्टर, प्रमुख थे का यह भी कहना था कि मनुष्य की उत्पत्ति इन्हीं महाद्वीपों पर हुई थी। ये दोनों महाद्वीप किसी भू-वैज्ञानिक हलचल की वजह से समुद्र के भीतर समा गए।

जब से पृथ्वी बनी है, तब से विनाश के कई चरण हुए हैं तथा कई प्रजातियां विलुप्त हुईं और नई आई भी हैं। विश्व की सभी जातियों एवं धर्मों में प्राचीन महाप्रलय का उल्लेख मिलता है। केवल धर्म ही नहीं, भू-वैज्ञानिक साक्ष्य भी पृथ्वी पर कई प्राचीन विनाशकारी हलचलों को दर्शाते हैं चाहे वे भूकंप के रूप में हों या ज्वालामुखी के रूप में या ग्लोबल वॉर्मिंग या हिमयुग के रूप में हों। आदिम जनजातियों में भी जल महाप्रलय का उल्लेख कहानियों के रूप में हुआ है। इसी क्रम में इन दो महाद्वीपों का उल्लेख भी प्राचीन तमिल साहित्य में पाया जाता है। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास, अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर हिन्द महासागर में स्थित। कुमारी कंदम' नामक द्वीप में हुआ था। हालांकि कुमारी कंदम या लेमुरिया को हिन्द महासागर में विलुप्त हो चुकी काल्पनिक सभ्यता कहा जाता है । इसे कुमारीनाडु के नाम से भी जाना जाता है । कुछ लेखक तो इसे रावण की लंका के नाम से भी जोड़ते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत को श्रीलंका से जोड़ने वाला राम सेतु भी इसी महाद्वीप में पड़ता है। तमिल पुनर्जागरणवादियों के अनुसार 'कुमारी कंदम' के पांडियन राजा का पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन था। दक्षिण भारत के लोकगीतों में इतिहास के साथ उस खो चुकी इस सभ्यता का वर्णन मिलता है। नतीजतन, जब इसके बारे में जानकारी देने वाले खोजकर्ता भारत के नगरों में पहुंचे, तब इस लोकगीत और कथा को बल मिला। तमिल लेखकों के अनुसार आधुनिक मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में न होकर हिन्द महासागर में स्थित 'कुमारी कंदम' नामक द्वीप में हुआ था। इसी महाद्वीप को Lemuri नाम इंग्लिश भूगोलवेत्ता फिलिप स्क्लाटरने 19 वीं सदी में दिया था सन 1903 मे वीजी सूर्यकुमार ने इसे सर्वप्रथम Kumari Nadu नाम दिया। कहा जाता है की यह कुमारी कंदम ही रावण के देश 'लंका' का विस्तृत स्वरुप है जो कि वर्तमान भारत से भी बड़ा था । हिन्द महासागर में एक बहुत बड़े महाद्वीप की संभावना को सबसे पहले ब्रिटिश भूगोलवेत्ता फिलिप स्क्लाटर ने बताया था। उन्होंने मेडागास्कर और भारत में बहुत बड़ी मात्रा में वानरों के जीवाश्मों के मिलने पर यहां एक नयी सभ्यता के होने का अंदेशा व्यक्त किया था। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम The Mammals of Madagascar था, जो कि 1864 में प्रकाशित हई थी। भूगोलवेत्ता वासुदेवन के अध्ययन के अनुसार, मानव सभ्यता का विकास अफ्रीका महाद्वीप में ना होकर कुमारी हिन्द महासागर के 'कुमारी नामक' द्वीप पर हुआ था। उनके अध्ययन कहते हैं कि आज से लगभग 14,000 साल पहले जब कुमारी कंदम जलमग्न हो गया तो लोग यहां से पलायन कर अफ्रीका, यूरोप, चीन सहित पूरे विश्व में फैल गए और कई नयी सभ्यताओं को जन्म दिया। ऐसा माना जाता है कि हिम युग के अंतिम सालों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया था जिसके कारण ग्लेशियरों का पिघलना शुरू हुआ और समुद्र का जल स्तर बहुत बढ़ गया और अंततः यह सभ्यता पानी में डूब गयी।

लुप्त हो चुके दो महाद्वीपों "लेमुरिया एवं मु' 'की अभी तक वैज्ञानिक पुष्टि नही हो पाई है। लेकिन विश्व के खोजकर्ताओं का दावा है की यह दोनों महाद्वीप पर सभ्यता काफी विकसित थी। हाल के वर्षो में मॉरिशस के पास हिन्द महासागर के नीचे एक खोया महाद्वीप पाया गया। ये प्राचीन महाद्वीप जो कभी भारत और मेडागास्कर के बीच में फैला हुआ था, अब हिंद महासागर के तल पर बिखरा हुआ है। ये प्राचीन महाद्वीप, जिसे मॉरिटिया के नाम से जाना जाता है, एक बार गोंडवाना सुपरकॉन्टिनेंट के दौरान मेडागास्कर को भारत से जोड़ता था। एक रोचक तथ्य यह सामने उभर कर सामने आया है की हमलोग की आगे की पीढ़ी शायद फिर लेमुरिया द्वीप पर वास करे। खोजकर्ताओं का मानना है की जिस तरीके से लेमुरिया द्वीप समुद्र के अन्दर समां गया शायद भविष्य मैं किसी प्लेट टेक्टोनिक या किसी भूगर्भीय हलचल की वजह से यह द्वीप समुद्र के ऊपर आ जाए। लेमुरिया महाद्वीप हिंद महासागर के नीचे एवं मु महाद्वीप प्रशांत महासागर के नीचे समा गया। खोजकर्ताओं की माने तो "मु" महाद्वीप 50,000 वर्ष पहले तक था एवं "लेमुरिया द्वीप" की उत्पत्ति एक लाख साल पहले हुई थी। जिस वक्त ये दोनों महाद्वीप समुद्र के नीचे समाये उस वक्त पृथ्वी का तापमान आज के तुलना में ज्यादा रहा होगा जिसके चलते हिमनदों के पिघलने से समुद्र का जलस्तर ऊंचा उठा एवं इन दोनों महाद्वीपों को धीरे धीरे अपने भीतर समां लिया। वैसे भी आज के बढ़ते तापमान की वजह से विश्व के कई छोटे छोटे द्वीप खतरें में आ गए है। पहले भी हमारे पृथ्वी पर कई बदलाव हुए आज जहां पर सुखी जमीन है वहां पहले समुद्र हुआ करता था। आज जहां रेगिस्तान है वहां पहले हरियाली हुआ करती थी। पृथ्वी पर प्राचीन काल के जिओलोजिकल विनाश के अवशेष आज भी मिलते है । एल्फ्रेड रसेल एवं एर्नेस्ट हेकेल का मानना था की मनुष्य की उत्पत्ति इन महाद्वीपों पर हुई थी। लेमुरिया शब्द लेमूर नामक जीव से आया जो बन्दर एवं गिलहरी का मिश्रित रूप है। लेमूर का मूल स्थान मेडागास्कर है लेकिन यह भारत एवं मलाया मे भी पाया जाता है। इसलिये यह माना गया की ये जीव तभी भारत पहुंचें होंगे जब कोई विशाल महाद्वीप हिंद महासागर में रहा होगा एवं जो भारत एवं मेडागास्कर के बीच में सेतु का काम किया।

आज सारे विश्व के वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं की आने वाले समय में पृथ्वी पर कई विनाशकारी बदलाव होंगे। कारण है ग्लोबल वार्मिंग। कई छोटे द्वीप समुद्र में समा जायंगे । कहीं सूखे की मार होगी तो कहीं अतिवृष्टि। कई नए जगह भूकंप प्रभावित होंगे जो पहले नही थे । यानि विनाश का एक नया रूप सामने आएगा।विनाश अगर होगा भी तो अचानक नहीं । विनाश की प्रक्रिया धीरे धीरे होती है जैसे पहले हुई थी।

झारखण्ड के मुंडाओं के मूल स्थान तथा उनके आव्रजन मार्ग की खोग में लेमुरिया सिद्धांत का उल्लेख हुआ है। एस सी रॉय ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। रॉय ने दक्षिण अफ्रीका एवं दक्षिण भारत के बीच एक लेमुरिया द्वीप की कल्पना की है जो अब जलमग्न हो चुका है। उन्होंने संभावना व्यक्त की है की मुंडा जाति लेमुरिया द्वीप से होती हुए भारत आई थी। इस प्रसंग में दक्षिण अफ्रीका के मेडागास्कर का नाम उल्लेखित हुआ है। इस मत के अनुसार मुंडाओं का मूल स्थान मेडागास्कर है और भारत आव्रजन "लेमुरिया द्वीप" से होते हुए हुआ है। अब सवाल यह उठता है की अगर यह दोनों महाद्वीप थे तो ये समुद्र में कैसे समा गए। क्या समुद्र के बढ़ते जलस्तर ने इनको अपने अन्दर समा लिया या किसी भुवैज्ञानिक हलचल के चलते यह महासागर के अन्दर चले गए । अभी भी इसपर खोज जारी है। यहां सवाल लेमुरिया या मु का नहीं है ।सवाल यह है की अगर पृथ्वी का तापमान यूं ही बढ़ता रहा तो आने वाले समय में कोई दूसरा लेमुरिया या मु जैसी घटना होने से इंकार नही किया जा सकता। ●

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विदेशी निवेश की जरूरत

गैरपारंपरिक ऊर्जा

मुरलीधर

रांची के गेतलसूद डैम में बेल्जियम की कंपनी ने सर्वे किया है। डैम में तैरता हुआ सोलर पैनल का एक प्लांट लगाया जायेगा, यह तैरता हुआ प्लांट पानी के बढने पर स्वतः ऊपर ऊठता जायेगा। इस प्लांट से 2020 तक 150 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। अगर ये सब जमीनी तौर पर पूरा होता है तो यह रांची ही नहीं झारखंड और देश के लिये एक उपलब्धि होगी।

सौर ऊर्जा की पर्यावरण अनुकूलता इसे विश्व स्तर पर स्वीकार्य बनाता है, और पर्यावरण की चिंता से दुनिया को जोड़ते हुए अपने लिए प्रतिबद्ध और अपरिहार्य भी। 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2022 तक 20 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के मकसद के साथ जवाहरलाल नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत की थी। यही लक्ष्य 5 साल बाद एक जुलाई, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में बढ़ाकर एक लाख मेगावाट कर दिया गया। इसी साल दिसम्बर में पेरिस समझौते के बाद स्वच्छ पर्यावरण के प्रति नियंतण्र जिम्मेदारी को स्वीकारते हुए भारत ने सौर ऊर्जा के त्वरित विकास की ओर कदम उठाने की कोशिश शुरू की। मोदी सरकार ने साल दर साल सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता स्थापित करने का जो लक्ष्य रखा था, उसके मुताबिक भारत के पास 2018-19 तक 45 हजार मेगावाट यानी 45 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता होनी चाहिए थी। मगर अब तक भारत 23 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता ही हासिल कर सका है। केंद्र सरकार का दावा है कि 40 गीगावाट की उत्पादन क्षमता के लिए निविदा और स्थापना (इंस्टॉलेशन) का कार्य जारी है। इस दावे पर यकीन कर पाना मुश्किल है और इस गति से एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा की उत्पादन क्षमता का लक्ष्य अगले 20 साल में भी पूरा नहीं हो पाएगा। इस सुस्त रफ्तार की वजह समझने की कोशिश करें तो बड़ी वजह है कि भारत को उन उपकरणों को आयात करना पड़ता है, जो सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता विकसित करने के लिए जरूरी हैं। इसके लिए डॉलर चाहिए। डॉलर की चुनौती से निपटने का तरीका यही है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अधिकतम एफडीआई यानी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हो। यही रफ्तार बहुत धीमी है। ग्रीन एनर्जी पर 2017 में 11 बिलियन डॉलर का निवेश आया। 2018 की छमाही तक यह आंकड़ा 7.4 बिलियन डॉलर था, मगर बाद में घटता चला गया। सरकार ने फंड की कमी से निपटने के लिए बजट में नवीनीकरण ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 3,762 करोड़ रु पये आवंटित किए। यहां तक कि अंतरिम बजट में भी 3,000.90 करोड़ रु पये का आवंटन किया। इसके बावजूद सौर ऊर्जा के उत्पादन की क्षमता के विकास में अपेक्षित गति प्राप्त नहीं हो सकी है। सौर ऊर्जा के विकास में जो बाधाएं हैं, उनमें महत्त्वपूर्ण यह भी है कि भारत के पास मास स्टोरेज यानी बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा के व्यापक संग्रहण की व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई। इस क्षेत्र में चीन ने आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है, और वह सौर ऊर्जा के निर्यात तक की स्थिति में आ चुका है। भारत के लिए सौर ऊर्जा का निर्यात अभी सपना है। सौर ऊर्जा की भारत में प्रति व्यक्ति खपत दुनिया में ऊर्जा खपत की एक तिहाई है।

मूल रूप से परंपरागत ऊर्जा ही यह जरूरत पूरी करती है। भारत ने 2030 तक ऊर्जा पर परंपरागत निर्भरता को 40 फीसदी तक कम करने का लक्ष्य रखा है। यह पेरिस समझौते के अनुरूप हानिकारक उत्सर्जक गैसों के उपयोग को रोकने के दायित्व और प्रतिबद्धता से जुड़ा है। मगर इस उद्देश्य का सीधा और समानुपातिक सबंध सौर ऊर्जा के विकास से है। चिंता की बात यह है कि इसमें भी भारत पिछड़ रहा है। भारत ने जो एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की क्षमता 2022 तक विकसित करने का लक्ष्य रखा है, उसमें से 40 हजार मेगावाट रूफटॉप सोलर एनर्जी के जरिए है, और बाकी ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा प्रॉजेक्ट के जरिए। देश में जो क्षमता 2015 के बाद से बीते चार साल में हासिल की गई है, उसमें रूफ टॉप सोलर एनर्जी का योगदान बेहद कम है। मौजूदा सौर ऊर्जा का यह महज 13 फीसद है। रूफ टॉप सौर एनर्जी के विकास से विद्युत वितरण से बचा जा सकता है। घरेलू और सार्वजनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए यह बेहद कारगर है। किन्तु, इसकी लगातार उपेक्षा चिंताजनक और आश्चर्यजनक है। प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि एक गीगावाट सौर ऊर्जा की उत्पादन सुविधा होने से 4 हजार प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होते हैं। इससे भी इस पर ध्यान देने की जरूरत थी। मगर बहु-प्रचारित योजना में सुस्ती ने 2022 तक एक लाख मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य को कई दशकों तक न पूरा होने वाला सपना बना दिया है। ●

पांच शहरों में चलेगा क्लीन एयर प्रोग्राम

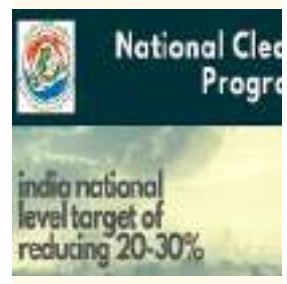

वायु प्रदूषण से जूझ रहे प्रदेश के पांच प्रमुख शहरों आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और लखनऊ को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पर्यावरण मंत्रालय ने बजट जारी किया है। आगरा में सड़कों की मशीन से सफाई और धुलाई के साथ निर्माण कचरे के निस्तारण के लिए 4.5 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर्स के लिए दो करोड़ रुपये, वाटर स्प्रिंकलर के लिए एक करोड़ रुपये और निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा के लिए 1.5 करोड़ रुपये आगरा नगर निगम को स्वीकृत किए गए हैं। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत पांच साल के लिए बजट मांगा गया है। इनमें एसटीपी के पानी से पौधों की धुलाई, सड़कों से धूल हटाने के लिए धुलाई, मशीन से सड़कों की सफाई, लोगों को जागरूक करने, तीन वाटर स्प्रिंकलर खरीदने, मोबाइल एनफोर्समेंट यूनिट, ग्रीन बफर बनाने, पौधरोपण, सिटी फोरेस्ट, पार्क, नर्सरी बनाने के लिए बजट मांगा गया है। ताजमहल के पास 90 ढाबों पर गैस आधारित तंदूर और सिलेंडर देने के लिए 22.5 लाख रुपये मांगे गए हैं।

दिल्ली : कैफे में बिक रही है प्योर हवा

दिल्ली के प्रदूषित हवा को देख कर अब कुछ कंपनियों ने इसका व्यावसायिक दोहन भी शुरू कर दिया है। ऑक्सीप्योर नामक कंपनी ने कैफे खोला है जहां 15 मिनट तक खुशबूदार हवा लेने के 300 से 500 रूपये तक चुकाने पड़ते हैं। इस कथित शुद्ध ऑक्सीजन में लेमन, दालचीनी, पुइीना, लेवेंडर वगैरह की खुश्बू उपलब्ध है। हालांकि ये जांच का विषय है कि ये हवा शुद्ध है या नहीं। अब तक हवा को शुद्ध करने के लिये एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन प्रदूषण का स्तर ऐसा है कि ये भी बेकार साबित हो रहे हैं इन एयरप्यूरीफायरों को लेकर भी कई जानाकरों का मानना था कि ये सिर्फ एक व्यावसायिक ठगी है, इन एयर प्यूफायरों से कोई खास फर्क नहीं पड़ता

दिल्ली ही नहीं कई और शहरों में भी है खतरनाक वायू प्रदूषण

- देश के 26 वायु प्रदूषित शहरों में बिहार के गया का भी नाम
- पटना तेरहवें स्थान पर
- वर्ष 2000 से ही दिल्ली है सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण वाला शहर

एजेंसियां :दिल्ली की जहरीली हवा कुछ दिनो से खबरों में हैं। यहां सांस लेने तक में मकलीफ हो रही है। हकीकत में तो सिर्फ दिल्ली ही नहीं दिल्ली जैसे कई शहर हैं जहां जहरीली हवा का कहर है, लेकिन चर्चा सिर्फ दिल्ली की हो रही है। 1 से 15 नवंबर के दौरान एनसीआर में आने वाले गाजियाबाद, नोएडा से लेकर जींद तक की हालत खराब रही। इसे लेकर विदेशों तक चर्चा हुई। मगर कोई भी इसका स्थाई समाधान नहीं ढूंढ पा रहा है। इसके पीछे का प्रमुख कारण यह भी है कि सभी का फोकस दिल्ली पर ही है। जबकि विशेषज्ञों के मुताबिक दिल्ली की हवा को सांस लेने लायक बनाने के लिए पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक सफाई करनी होगी। इसके लिए हमें भविष्य को देखते हुए रणनीति अपनानी होगी।

देशभर में सिर्फ दिल्ली के प्रदूषण को लेकर चर्चा है जबकि उत्तर भारत से निकलने वाली नदियों के किनारे बसे कई शहरों में यह समस्या है। 'अर्बन साइंस' ने 26 शहरों की वायु गुणवत्ता का अध्ययन किया। इसमें गाजियाबाद की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित मिली। विशेषज्ञों का कहना है कि यदि साल 2024 तक पीएम 2.5 का स्तर 25 फीसदी तक कम करना है तो इसके लिए 'एयरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण' की आवश्यकता है। एयरशेड प्रबंधन दृष्टिकोण ऐसा प्रयास है, जिसे भविष्य में वायु प्रदूषण की समस्या से बचने और हवा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। 300 करोड़ की लागत से केंद्र सरकार द्वारा शुरू किए

देश के सबसे प्रदूषित 26 शहर

1 गाजियाबाद	14 कुरुक्षेत्र
2 नोएडा	15 मुरादाबाद
3 ग्रेटर नोएडा	16 मुजफ्फरनगर
4 जिंद	17 वाराणसी
5 दिल्ली	18 पटियाला
6 हिसार	19 गया
7 पानीपत	20अमृतसर
8 गुड़गांव	21 जलंधर
9 फरीदाबाद	22लुधियाना
10 कानपुर	23आगरा
11 मेरठ	24 चंडीगढ़
12 लखनऊ	25कोलकाता
13 पटना	26 पंचकुला

गए राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (ठउअढ) के लक्ष्य के तहत ऐसा करना जरुरी होगा। साल 2000 से लेकर 2018 तक देश भर में पीएम 2.5 का स्तर देखें, तो दक्षिण भारत के मुकाबले उत्तर भारत में वायु प्रदूषण काफी अधिक है। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा के शहरों की हवा में पीएम 2.5 की मात्रा 10 से लेकर 50 तक है। कर्नाटक और आंध्रप्रदेश में भी वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर नहीं है। वहीं तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों और कर्नाटक के कुछ शहरों की हवा में पीएम 2.5 की औसतन मात्रा 20 से भी कम है।

उत्तर भारत में स्थिति बहुत खराब

उत्तर भारत की नदियों किनारे बसे शहरों की स्थिति ज्यादा खराब है। हवा में पीएम 2.5 की औसतन मात्रा यहां 80 से 90 के बीच रही है। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के शहरों की हवा अपेक्षाकृत ज्यादा प्रदूषित है। वहीं, पूर्वोत्तर राज्यों में वायु प्रदूषण की स्थिति ज्यादा गंभीर नहीं है। पूर्वोत्तर भारत के कई शहरों की हवा में पीएम 2.5 की औसतन मात्रा 20 से भी कम रही है। दिल्ली की एक संस्था 'क्लाइमेट ट्रेंड्स' की ओर से आयोजित एक परिचर्चा कार्यक्रम में विशेषज्ञों और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के प्रतिनिधियों ने राज्यों के बीच बेहतर सहयोग और ऐसे छोटे शहरों पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने की मांग की, जहां उच्च उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। आईआईटी दिल्ली के शिक्षक और स्वच्छ हवा अनुसंधान केंद्र के समन्वयक डॉ साग्निक डे का कहना है कि दिल्ली में उच्च प्रदूषण की समस्या एक दशक पहले सर्दियों में प्रचलित नहीं थी क्योंकि पड़ोसी शहरों और शहरों से उत्सर्जन इतना अधिक नहीं था। हाल के दिनों में यह बहुत ज्यादा हो गया है और अब नियंत्रण से बाहर होता जा रहा है। डॉ. साग्निक कहते हैं कि देशभर में गंगा के मैदानी इलाकों को एक विशाल क्षेत्र मानने की आवश्यकता है और वायु गुणवत्ता सुधार की योजना केवल एक शहर के लिए नहीं, बल्कि इस पूरे विशाल क्षेत्र के लिए बनाने की जरुरत है। डॉ. डे का कहना है कि कि वायु प्रदूषण की समस्या को व्यापक रूप से दूर करने के लिए, हमें क्षेत्रों में हवा और उनके प्रदूषण के अनुसार एयरशेड के परिसीमन की जरूरत है। शहरी कार्ययोजना बनाने के दौरान इसे प्रभावी बनाने के लिए एयरशेड प्रबंधन रणनीति को भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक इन इलाकों में सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरा क्षेत्र बेहद जटिल भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थितियों की वजह से विपरीत परिस्थितियों का निर्माण करता है।

शहरी विज्ञान के सीईओ रौनक सुतारिया कहते हैं कि पूरे क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने की आवश्यकता है। पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ के स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ के प्रोफेसर डॉ. रवींद्र खाईवाल ने प्रदूषण कम करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किए जाने का सुझाव दिया। उनका कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए जन सहभागिता के बिना योजनाएं सफल नहीं हो सकती। ●

पहले दूसरे चरण के चुनाव के लिये वोटर्स स्लिप की डिलीवरी शुरू

घर पर फोटो वोटर्स स्लिप नहीं मिलने पर मतदाता वोटर्स हेल्पलाइन नंबर-1950 पर कर सकतें हैं शिकायत

अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि विधानसभा चुनाव-2019 को लेकर सभी मतदाताओं के घर पर फोटो वोटर्स स्लिप की डिलीवरी की जानी है। इस सिलसिले में पहले और दूसरे चरण में जिन विधानसभा सीटों के लिए मतदान होना है, वहां मतदाताओं के घर पर फोटो वोटर्स स्लिप का वितरण शुरु कर दिया गया है। अगर किसी मतदाता को किन्हीं वजहों से घर पर फोटो वोटर्स स्लिप नहीं मिलता है तो वे अपनी शिकायत वोटर्स हेल्पलाइन नंबर-1950 पर दर्ज करा सकते हैं। पहले चरण में 13 सीटों के लिए 30 नवंबर और दूसरे चरण में 20 सीटों के लिए 7 दिसंबर को मतदान होना है।

5 करोड़, 53 लाख,14 हजार 561 रुपए की संदिग्ध/ अवैध सामग्रियां हो चुकी जब्त

रांची:आदर्श चुनाव आचार संहिता लगने के उपरांत संदिग्ध नकदी, अवैध शराब, जावा-महुआ, गांजा, ओपियम, डोडा, ब्राउन शुगर और बहुमूल्य धातु समेत कई अन्य सामग्री जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनय कुमार चौबे ने बताया कि विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा होने के बाद से 21 नवंबर 2019 तक 5,53,14,561 रुपए (पांच करोड़, तिरपन लाख, चौदह हजार पांच सौ इकसठ रुपए)) की संदिग्ध नकदी, अवैध शराब और गांजा समेत कई अन्य सामग्रियां जब्त की जा चुकी है। इसमें 2,12,03,281 रुपए (दो करोड़, बारह लाख, तीन हजार दो सौ इक्कासी रुपए) नकद जब्त किए गए हैं। साथ ही 1,92,64,272 रुपए (एक करोड़, बयान्बे लाख, चौसठ हजार दो सौ बहत्तर रुपए) कीमत का अवैध शराब और महुआ जब्त किया गया है।

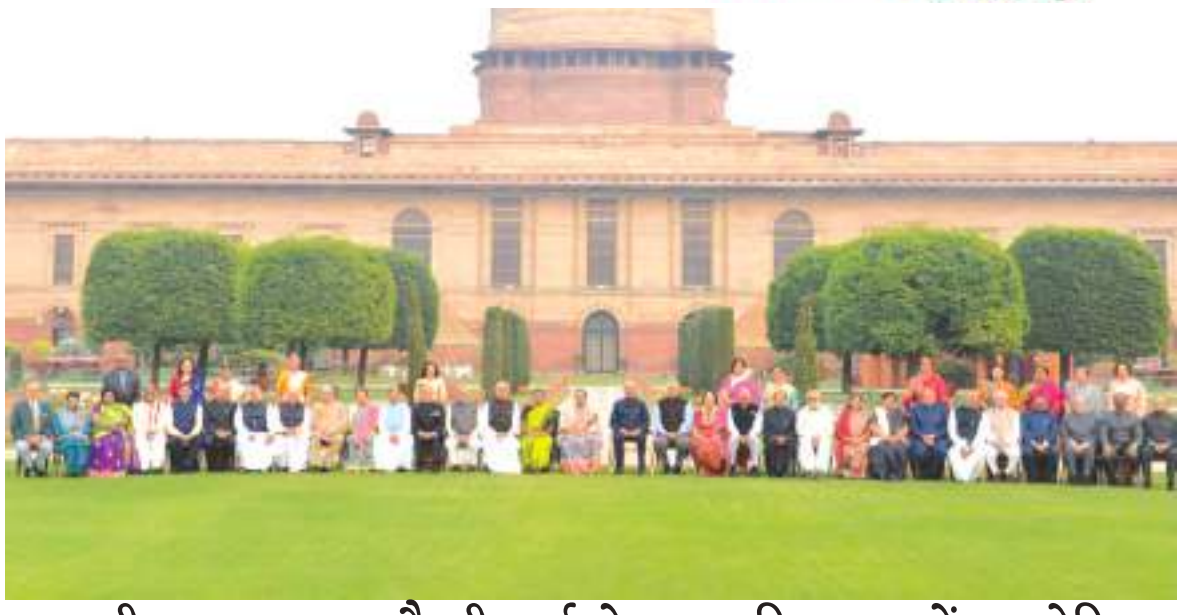

माननीया राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित राज्यपाल सम्मेलन में भाग लिया।

चुनाव के प्रति अनुकूल वातावरण तैयार करे मीडिया:मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी

- प्रसार भारती द्वारा झारखंड विधानसभा चुनाव-2019 को लेकर उन्मुखीकरण कार्यशाला का हुआ आयोजन
- नैतिक मतदान के लिए मतदाताओं को करें जागरुक
- लोगों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जानकारी लगातार दे
- मीडिया, समाचारों के संकलन में निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संतुलन बनाए रखें

संवाददाता

रांची :विधानसभा चुनाव के सफल संचालन में मीडिया का अहम रोल है। मीडिया की पहुंच जन-जन तक होती है, अतः मतदाताओं को जागरुक करने में उनकी भूमिका और बढ़ जाती है। श्री विनय कुमार चौबे, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने आज विधानसभा चुनाव को लेकर प्रसार भारती की ओर से आयोजित उन्मुखीकरण कार्यशाला में मीडिया से चुनाव के प्रति अनुकूल वातवरण तैयार करने को कहा, ताकि ज्यादा से ज्यादा मतदाताओं की निर्वाचन प्रक्रिया में सहभागिता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन और आकाशवाणी का अपना ही महत्व है। पब्लिक ब्रॉडकास्टर होने के नाते दूरदर्शन और आकाशवाणी मतदाताओं को इस तरह जागरुक करें कि वह बिना किसी भय, पक्षपात, डर और प्रलोभन में आए नैतिक मतदान करें। समाचारों के माध्यम से लोगो को चुनाव से संबंधित जानकारी लगातार देते रहें। इसके अलावा मतदाताओं को निर्वाचन आयोग के नए इनिशिएटिव और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की भी जानकारी दें।

स्वीप एक्टिविटीज में मीडिया निभाएं सशक्त रोल

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि विभिन्न माध्यमो द्वारा चलाए जा रहे स्वीप कार्यक्रमों को लेकर मीडिया सशक्त रोल निभाए. उन्होंने कहा कि स्वीप का मकसद सिर्फ मतदाताओं को मतदान प्रतिशत बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि निर्वाचन प्रक्रिया में उन्हें शामिल करने के लिए जागरुक भी करना है। इसके साथ मतदाताओं को नैतिक मतदान के लिए प्रेरित करना भी इसका एक अहम उदेश्य है। इससे भारतीय लोकतंत्र को मजबूती मिलेगी।

.....पेज 1 का शेष

बीएयू में (कास्ट) प्रोजेक्ट का प्रीलांच

न्यूजीलैंड पेऑस्ट्रेलिया एवं केन्या आदि देशों में अद्यतन तकनीकों से परिचित कराने के लिए भेजा जायेगा. इस परियोजना से राज्य में कृषि, पशुपालन, वानिकी, उद्यान, कृषि अभियांत्रिकी, दुग्ध प्रौद्योगिकी एवं मत्स्यिकी विज्ञान आदि विषयों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बीएयू कुलपति ने कहा कि परियोजना से 24 जिलों में विभिन्न समेकित कृषि मॉडल के सत्यापन और उन्हें पूर्णता देने के अलावा राष्ट्रीय स्तर पर समेकित कृषि मॉडल पर एक ज्ञान हब को विकसित करने में मदद मिलेगी। इस कार्य अंतर्राष्ट्रीय / निजी संगठन के साथ जीवंत सम्बन्ध को स्थापित किया जायेगा। उन्होंने बताया कि अगले 3 वर्षों में परियोजना के समग्र अपेक्षित परिणाम/आउटपुट, उत्कृष्टता और स्थानीय,राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संस्थागत प्रदर्शन और विशेष व्याख्यान के माध्यम से छात्रों और संकायों के लिए यह उत्कृष्टता के केंद्र साबित होगा। किसान, कृषि महिलाएँ, केवीके के वैज्ञानिक / विस्तार कार्यकर्ता भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।इस अवसर पर परियोजना के प्रधान समन्यवयक डॉ एमएस मल्लिक ने योजना के अवयवों पर प्रकाश डाला। मौके पर किसान, स्वंयसेवी संस्था एवं उद्योगों के प्रतिनिधियों ने भी अपने विचारों को रखा। स्वागत डॉ नरेंद्र कुदादा, संचालन डॉ सुश्री निभा बाडा तथा धन्यवाद

में पीजी और पीएचडी छात्रों की भी भागीदारी होगी। इसमें उच्च शिक्षा के क्षेत्र में छात्रों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में तकनीकी प्रशिक्षण /एक्सपोज़र विज़िट और ज्ञान साझा करने का अवसर मिलेगा, नवाचार तकनीकों को प्राथमिकता और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को गति देने के लिए राष्ट्रीय / डॉ बीके झा ने दिया. मौके पर डॉ एमएस यादव, डॉ डीएन सिंह, डॉ एमपी सिन्हा, डॉ एमके गुप्ता, ई. डीके रूसिया, डॉ राघव ठाकुर, डॉ एमएच सिद्दिकी, डॉ एके सिंह, सुशील प्रसाद, डॉ अनिल कुमार, डॉ आरबी साह सहित विवि वैज्ञानिक, किसान, स्वंयसेवी संस्था एवं उद्योगों के प्रतिनिधि भी मौजूद थे।

स्वास्थ्य व सिलकोसिस जांच शिविर आयोजित

संवाददाता

रांची :सदर अस्पताल में असंगठित क्षेत्र के खानों में काम करने वाले कामगार तथा संविदा कर्मियों का ... भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय रांची क्षेत्र तत्वावधान में आयोजित किया गया । भारत सरकार के श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत खान सुरक्षा महानिदेशालय रांची क्षेत्र तत्वावधान में व्यवसायिक स्वास्थ्य व सिलकोसिस जांच परीक्षण शिविर का आयोजन सदर अस्पताल गुमला में किया गया। जिसमें गुमला जिला अंतर्गत आने वाले असंगठित क्षेत्र के खानों में काम करने वाले कामगार तथा संविदा कर्मियों का स्वास्थ्य जांच किया गया । जिसमें कार्य करने के दौरान होने वाली किसी भी व्यवसाय संबंधी स्वास्थ्य समस्या का पता लगाया जा सके तथा उसका सही समय पर इलाज हो सके। शिविर में कुल 30 कामगारों व श्रमिकों की जांच की गई। इस कार्यक्रम का आयोजन नियमित अंतराल पर किया जाता है। कार्यक्रम में जिला के सिविल सर्जन डॉ विजय भेंगरा की उपस्थिति में चिकित्सक डॉ राजेश कुमार द्वारा जांच किया गया। शिविर में खान महानिदेशालय रांची क्षेत्र के उपनिदेशक एम.के. गुप्ता, हिंडालको के वरीय महाप्रबंधक मनोज कुमार नायक, हिंडालको के चिकित्साधिकारी डॉ. ओपी दुबे, वरीय प्रबंधक अमर भारती आदि उपस्थित रहे।

पथ निर्माण विभाग और अजजा, अजा, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग विभाग की प्रगति और कार्य योजना की समीक्षा में बोले मुख्य सचिव डॉ.डी. के. तिवारी

हाईवे से थोड़ा हटकर यात्री सुविधा केंद्र बनाए

रांची: मुख्य सचिव डॉ. डीके तिवारी ने हाईवे (राज्य की मुख्य सड़कें) पर यात्रियों के लिए सुविधा केंद्र बनाने की योजना पर काम करने का निर्देश पथ निर्माण विभाग को दिया है। इसके लिए प्राधिकृत समिति में प्रस्ताव लाने को कहा है। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान सबसे ज्यादा शौचालय की कमी महसूस की जाती है। खासकर महिलाओं को शौचालय के अभाव में काफी परेशानी होती है। इसके लिए उन्होंने मुख्य सड़कों से सटे 200-250 मीटर हटकर यात्री सुविधा केंद्र बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि यह केंद्र प्रत्येक 50 से 100 किलोमीटर की दूरी पर हो, ताकि यात्री वहां रुक कर फ्रेस हो सकें। कुछ खा-पी सकें और थोड़ी सी यात्रा की थकान भी दूर कर सकें। उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर सबसे पहले रांची-पटना, रांची-जमशेदपुर मार्ग पर इसे लागू करने पर बल दिया। उन्होंने हाईवे पर माइल स्टोन के माध्यम से सबसे नजदीक के स्थान के साथ राह में पड़नेवाले मुख्य स्थानों की दूरी दर्शाने का निर्देश दिया। वहीं सड़क किनारे विभिन्न सूचनाएं, प्रेरक स्लोगन आदि से जुड़े साइनेज तकनीकी विशिष्टियों और आइआरसी के अनुरूप लगाने का भी निर्देश दिया। मुख्य सचिव झारखंड मंत्रालय में पथ निर्माण विभाग की तीन वर्षों की योजनाओं की प्रगति और आगामी 100 दिनों की कार्ययोजना की समीक्षा कर रहे थे।

रोड जंक्शन को आधुनिक करें

मुख्य सचिव ने शहर में रोड जंक्शन (गोलंबर) को सुगम यातायात के लिए आधुनिक बनाने का निर्देश दिया। कैसे करना है, इसे लेकर उन्होंने पावर प्रजेंटेशन के माध्यम से टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि शहर के गोलंबरों के पास आवागमन के लिए ऐसी व्यवस्था करें कि वाहन या तो सीधे निकल जाएं, या कुछ सेकेंड के लिए ही उसे रुकना पड़े। इसके लिए रांची के किसी एक मार्ग के गोलंबर पर तात्कालिक रूप से इसे विकसित करने पर बल दिया। साथ ही शहर से अनावश्यक ब्रेकर हटाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जहां जरूरी हो, वहां नियमानुसार तकनीकी विशिष्टिओं के अनुसार स्टैंडर्ड स्पीड ब्रेकर बनाएं।

ऊपरी परत हटाकर करें सड़कों का सुदृढ़ीकरण

मुख्य सचिव ने पथ निर्माण विभाग को स्पष्ट निर्देश दिया कि आगे से सड़क निर्माण में यह ध्यान रखें कि सड़क की मूल ऊंचाई नहीं बढ़े। उन्होंने निर्देश दिया कि पहले से बनी सड़क की ऊपरी परत को हटाकर (मिलिंग) ही सड़क निर्माण करें। कहा, सड़क पर परत-दर-परत चढ़ाते जाने से नालियों से जल निकासी में दिक्कत के साथ आवासीय भवनों, घरों में बारिश का पानी घुसने की भी समस्या आती है। वहीं उन्होंने विभागीय स्तर से सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर भी फोकस करने का निर्देश दिया।

इंजीनियर्स एकेडमी का गठन करें

मुख्य सचिव ने कहा कि अभियंताओं के अपेक्षित प्रशिक्षण के अभाव में उनका समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। वहीं योजनाओं के क्रियान्वयन तथा गुणवत्ता नियंत्रण में भी विभाग को अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए उन्होंने इंजीनियर्स एकेडमी के गठन का निर्देश दिया। कहा, आइएएस अधिकारियों की तरह राज्य के अभियंताओं को भी लगातार हो रहे तकनीकी बदलाव के अनुसार प्रशिक्षण की व्यवस्था करें।

शोर से पक्षी छोड़ रहे हैं गाना-चहचहाना और प्रजनन

देवाशीष

हाल में राजस्थान का सांभर झील हजारो पक्षियों के लिये कब्रगाह साबित हुआ है। अब तक बीस आप्रवासी हजार पक्षी सांभर झील में मर चुके हैं और वैज्ञानिकों का कहना है कि यह संख्या पचास हजार तक पहुंच सकती है। इस बीच एक दुखद तथ्य यह भी सामने आया है कि ध्वनि प्रदूषण के कारण पक्षियों ने गाना चहचहाना और प्रजनन करना कम कर दिया है। मनुष्यों के सर्वशक्तिमान होने का दंश आज सभी जीवों को झेलना पड़ रहा है।

जर्मनी के शोधार्थियों ने म्युनिख शहर के शोर भरे इलाके और शांत इलाके में अलग-अलग रह रहे जेबरा फिंच पक्षी पर शोध किया और कई चौंकाने वाले तथ्य प्रस्तुत किए

बढ़ते ध्वनि प्रदूषण से पक्षियों का जीवन बेहद प्रभावित हो रहा है। उनमें प्रजनन की शक्ति घट रही है और साथ ही उनके व्यवहार में भी परिवर्तन आ रहा है। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। यह अध्ययन जर्मनी के मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर ऑर्निथोलॉजी के शोधार्थियों ने किया है। उन्होंने जेबरा फिंच नाम के पक्षी पर अध्ययन किया और पाया कि ट्रैफिक के शोर से उनके रक्त में सामान्य ग्लकोकार्टिकोइड प्रोफाइल में कमी हुई और पक्षियों के बच्चों का आकार भी सामान्य चूजों से छोटा था। अध्ययन में दावा किया गया है कि ट्रैफिक के शोर की वजह से पक्षियों के गाने-चहचहाने पर भी फर्क पड़ता है।

यह अध्ययन कंजर्वेशन फिजियोलॉजी नामक पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अध्ययन में पक्षियों के दो समूह को

शामिल किया गया। इनमें एक समूह वह था, जो जर्मनी के राज्य बावरिया की राजधानी म्युनिख के एक शोर भरे इलाके में रहता है, जबकि दूसरा समूह शांत इलाके में रहता है। यह अध्ययन पक्षियों के प्रजनन काल के दौरान किया गया।

जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि पहली प्रजनन अवधि के अंत के कुछ समय बाद दोनों समूहों के समान जोड़ो के लिए शोर की स्थिति बदल दी गई। शोधकर्ताओं ने दोनों परिस्थितियों में प्रजनन अवधि के दौरान, पहले और बाद में हार्मोन में तनाव के स्तर को दर्ज किया। इसके अलावा, उन्होंने (इम्यून फंक्शन) प्रतिरक्षा कार्य और प्रजनन की सफलता के साथ-साथ चूजों की वृद्धि दर को भी देखा। उन्होंने पाया कि जब वे शांत वातावरण में प्रजनन कर रहे थे, तब पक्षियों के खून में कॉर्टिकोस्टेरॉन का स्तर ट्रैफिक के शोर में प्रजनन कर रहे पक्षियों की तुलना में कम था। यह आश्चर्यजनक था क्योंकि तनाव अक्सर कॉर्टिकोस्टेरॉन के उच्च स्तर का परिणाम होता है, एक हार्मोन जो तनावपूर्ण अनुभवों के दौरान चयापचय क्रिया में शामिल होता है।

प्रमुख अध्ययनकर्ता सू एनी ज़ोलिंगर कहते हैं, शांत वातावरण में प्रजनन करने वाले पक्षियों में, प्रजनन के पूरे मौसम में उनका आधारभूत कॉर्टिकोस्टेरॉन कम रहता है। इससे पता चलता है कि जिन पक्षियों को शोर में रहने की आदत नहीं थी उनके प्रजनन चक्र के दौरान उनके हार्मोन का स्तर उपर-नीचे होता है अर्थात असामान्य पाया गया था। वहीं इसके विपरीत जो शांत वातावरण में इस प्रक्रिया से गुजरते हैं उनके हार्मोन का स्तर सामान्य पाया गया था। जिन चूजों के माता-पिता ट्रैफिक के शोर के संपर्क में थे, उनके चूजे शांत वातावरण में रहने वाले माता-पिता की तुलना में छोटे थे। हालांकि, एक बार शोरगुल की स्थिति में रह रहे चूजों के बड़े होकर घोंसला छोड़ देने के पशचात, वे फिर शांत जगहों पर घोंसले बनाने में कामयाब रहते हैं। हालांकि, शोधकर्ता ने संतानों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभावों को नहीं लिया है।

ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले एक अध्ययन से पता चला है कि ट्रैफ़िक के शोर के संपर्क से युवा ज़ेबरा फ़िंच पक्षी में टेलोमेयर क्षति में तेजी आई है, जिस-का अर्थ है कि इन पक्षियों का जीवनकाल छोटा होने की आशंका है। हालांकि घोंसले में चूजों की संख्या पर यातायात के शोर का कोई प्रभाव नहीं था।

पक्षियों के साथ अध्ययन आम तौर पर यातायात से जुड़े अन्य कारकों, जैसे कि रासायनिक प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और शहरी क्षेत्रों में पाए जाने वाले अन्य भिन्नताओं को शामिल करने के लिए किया गया था, उदाहरण के लिए पक्षी समुदायों की संख्या और संरचना, निवास स्थान की संरचना, खाद्य प्रकार और उसकी उपलब्धता आदि थे।

शोध समूह के मुख्य अध्ययनकर्ता हेनरिक ब्रम कहते हैं, हमारे आंकड़े बताते है कि शहरी परिवेश की अन्य सभी गड़बड़ियों के बिना यातायात (ट्रैफिक) का शोर, पक्षियों के शरीर क्रिया विज्ञान को बदल देता है और उनके विकास पर प्रभाव डालता है। इसका मतलब यह है कि पक्षियों की प्रजातियां जो पहली नज़र में शहरों में अच्छी तरह से मुकाबला करती दिखती हैं, ट्रैफ़िक के शोर से प्रभावित हो सकती हैं।

सीएमपीडीआई द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन

रांची : सीएमपीडीआई के क्षेत्रीय संस्थान-3, रांची के ओरला ड्रिलिंग कैम्प के तत्वावधान में निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के अंतर्गत निःशुल्क चिकित्सा शिविर-सह-एच0आई0वी0/एड्स जागरूकता शिविर का आयोजन श्रमिक मध्य विद्यालय, तोपा में किया गया । चिकित्सा शिविर डॉ0 ओम प्रकाश एवं उनकी टीम द्वारा संचालित किया गया जबकि एच0आई0वी0/एड्स जागरूकता शिविर का संचालन झारखंड राज एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा किया गया। इस मौके पर वरीय प्रबंधक (कार्मिक) अश्विनी कुमार मिश्रा, ओरला कैम्प प्रभारी शंभू कुमार, सीएमयू सचिव विजय कुमार एवं विद्यालय के प्राचार्य लोकनाथ महतो उपस्थित थे।

इस चिकित्सा शिविर में आसपास के ग्रामीणों तथा स्कूली छात्र एवं छात्राओं की सामान्य जांच की गई। इस चिकित्सा शिविर में सीएमपीडीआई के चिकित्सा अधीक्षक डॉ0 ओम प्रकाश ने ग्रामीणों तथा स्कूली छात्र एवं छात्राओं की सामान्य

जांच की। जांचोपरांत आवश्यकतानुसार 212 ग्रामीणों तथा बच्चों के बीच आयरन, विटामिन्स, ए0डी0 कैप्सुल, कृमि की दवा, कैल्सियम की खुराक/दवा निशुल्क वितरित की गयी।

फोटो न्यूज

अच्छाई और खुबसूरती किसी प्रतिकूल स्थिति में भी पनप ही जाती है।

ये कोई दलदल या तालाब नहीं है बल्कि रातूरोड पिस्का मोड़ से आगे पंडरा पुल के नीचे से होकर बहने वाली नदी है जो यहां से कांके डैम में जाकर मिल जाती है। अगर इसे साफ कर दिया जाये, इससे जलकुंभी को हटा दिया जाये तो यह डैम के लिये जल का बड़ा स्त्रोत बन जायेगी। फोटो : मनोज

लाजवाब औषधीय फूल है गेंदा

राजन कुमार

पूजा पाठ से लेकर शादी विवाह स्वागत और आयोजन गेंदे के फूलों के बगैर पूरी नहीं होती। इन सभी मौकों पर हमें यह आदत सी है गेंदे के फूलों की पस्थिति देखने की। कुछ दशक पहले तक सिर्फ जाड़ों में खिलने वाला गेंदा अब बहुत ही आधुनिक और व्यावसायिक महत्व का फूल हो गया है और इसकी व्यावसायिक खेती खेती बंगाल के बाद झारखंड बिहार में भी खूब हो रही है। गेंदा बहुत ही उपयोगी एवं आसानी से उगाया जाने वाला फूलों का पौधा है। यह मुख्य रूप से सजावटी फूल है लेकिन इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं। मख्यतः यह फूल, माला एवं सजावट के लिए उगाया जाता है। मुर्गियों के दाने में भी यह पीले रंग के लिये उपयोग किया जाता है। इसके फूल बाजार में खुले एवं मालाएं बनाकर बेचे जाते हैं। गेंदे की विभिन्न ऊंचाई एवं विभिन्न रंगों के होने से यह शादी-विवाह में मण्डप सजाने में भी अहम् भूमिका निभाता है।

यह क्यारियों एवं हरबेसियस बॉर्डर के लिए अति उपयुक्त पौधा है। भारत में मुख्य रूप से अफ्रीकन गेंदा और फ्रेंच गेंदा की खेती की जाती है। इसे गुजराती भाषा में गलगोटा और मारवाड़ी भाषा में हंजारी गजरा फूल भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे ***मेरीगोल्ड*** कहते हैं। वनस्पति शास्त्र में इसका वैज्ञानिक नाम **टैगेटा पैत्युला** है और यह एस्टेरेसी कुल का फूल है। इसका मूल उत्तर अमेरिका महादेश माना गया है। इसे खिलने के लिये धूप की आवश्यकता होती है।

पिछले कुछ सालों में गेंदे की बहुत सारी किस्में विकसित की गयी हैं जो पहले नहीं दिखती थीं, पहले सिर्फ देशी गेंदे की ही कुछ किस्में उपलब्ध थीं जो हजारा, और जीरा हजारा नाम से जानी जाती थीं जो हमारे घर आंगन की शोभा बढाते थे । ये सिर्फ दो रंगों नारंगी और पीले रंग की होती थीं। इसके अलावा गेंदे की एक छोटी किस्म थी जो कत्थई रंग की होती है और जाड़े के अलावा भी हमेंशा खिलती रहती है। आज बाजार में सैकड़ो किस्म के गेंदे के फूल के पौधे उपलब्ध हैं जो सालो भर खिलते हैं। गेंदे के फूल में एक मादक सी सुगंध भी होती है।

घर आंगन में जरूर लगायें गेंदा

फूलों प्रकृति की अनुपम उपहार हैं और वैज्ञानिक तौर पर भी यह साबित हो चुका है कि इन्हें निहारने से तनाव और अवासाद घटता है। चीन में तो गुलदाउदी के फूलों पर शोध हुआ और यह पाया गया है कि आत्महत्या पर उतारू लोगों को भी जब विभिन्न प्रकार के गुलदाउदी के फूलों वाले जगह पर रखा गया तो उनका अवासाद जाता रहा।

पहले गांवों में देसी गेंदे के फूलों को सूखा कर रख लिया जाता था और अगले वर्ष मौसम में उसके बीजों को बो कर नये पौधे उगाये जाते थे जिन्हें घर आंगन में लगाया जाता था। आज हाइब्रीड गेंदों की भरमार है जिसमें छोटे पौधे में ही बड़े फूल खिलते हैं। नर्सरियों में इसके पौधे बिकते हैं। ये देखने में सुंदर होते हैं पर इनमें खुशबू बहुत कम होती है। लेकिन देसी गेंदे की बात ही अलग है। देसी हजारा या जीरा हजारा गेंदे के पौधे तीन चार फुट तक बड़े हो जाते हैं और इनमें देर से फूल खिलते हैं लेकिन इनमें एक मादक गंध होती है और इनकी खुबसुरती के सामने हाइब्रीड गेंदे कही नहीं टिकते। गेंदे के पौधों को धूप मिलना जरूरी है, तभी यह अच्छे से खिलेंगे। इसके अलावा फूल पौधों और बागवानी के प्रेमियों से भी इसे सही तरीके से लगाने का तरीका पूछ सकते हैं।

मारीगोल्ड बिस्किट का आकार गेंदे के फूलों के बनावट से ही लिया गया है और इसी लिये इस बिस्किट का नाम भी मारीगोल्ड रखा गया। इसके अलावा गेंदे के फूल का जलवा भारतीय सिनेमा में भी देखने को मिलता है। मन्ना दा का एक चर्चित गाना भी था फूलगेंदवा ना मारो सलमान खान की एक फिल्म का नाम ही था मारीगोल्ड अभिषेक बच्चन की फिल्म का गाना ससुराल गेंदा फूल भी बहुत चर्चित हुआ था।

औषधीय गुणों से भरपूर है गेंदा

गेंदा महज एक फूल नहीं है, बलिक एक औषधी भी है। गेंदे के फूल को गरीबों का केसर भी कहा जाता ह गौर करें तो हम पाते हैं कि यह बचपन से हमारा साथी रहा है। खेलते कूदते वक्त अगर हमें कहीं चोट लग जाती थी तो हम कटे छिले जगह पर गेंदे की पत्तियों को मसल कर उसके रस को लगा लिया करते थे जो एंटीसेप्टिक का काम करती थीं। गेंदा कटे फटे घावों को इंफेक्सन से बचाता है। कई ऐसे लोग भी मिल जायेंगे जो बताते हैं कि दवा से घाव ठिक नहीं हुआ पर रोज गेंदे के पत्त्यिों के रस को लगाने से उनका घाव ठिक हो गया। झारखंड में पहले गेंदे की आवक बंगाल से होती थी लेकिन अब राज्य में भी गेंदे के फूलों की खेती हो रही है और हॉर्टीकल्चर विभाग ने इसमें किसानों की काफी मदद की है।

- गेंदे के फूल हानिकारक कीटाणुओं और कीड़ों को दूर रखते है। इसे लगाने से मलेरिया वाले मच्छर भी भाग जाते है।
- इसकी पत्ती का रस कान में डालने से कान का दर्द दूर हो जाता है। तेल गर्म कर उसमे दो तीन गेंदे की पत्तियाँ, अजवाइन और लहसुन डालकर छान लें। यह तेल कान में डालने से दर्द चला जाता है।
- गेंदा के फूलों का रस नारियल तेल के साथ मिलाकर उससे हल्की-हल्की मालिश करके नहा लिया जाए तो सिर में हुए किसी भी तरह के संक्रमण, फोड़े- फुंसियों में आराम मिल जाता है।
- त्वचा की कई समस्याओं में गेंदे की पत्तियों के रस को लाभकारी माना गया है। इसी लिये इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधनों को बनाने में भी किया जाता है।
- गेंदे के फूल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो दर्द में आराम दिलाने का काम करते हैं। घाव भरने में भी ये कारगर औषधि की तरह प्रभावी है। अगर किसी को अल्सर की समस्या है तो गेंदे के फूल की चाय पीना उसके लिए विशेषतौर पर फायदेमंद रहेगा।
- गेंदे के फूल का इस्तेमाल रंजक के रूप में भी किया जाता है।
- गेंदे के फूल का इस्तेमाल एंटी-बायोटीक के रूप में किया जाता है।
- गेंदे के फूल में कई ऐसे एंटी-ऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं। जो आंखों से जुड़ी कई तरह की बीमारियों में फायदेमंद साबित होते हैं।
- गेंदे का फूल एक बेहतरीन सौंदर्य उत्पाद है। ये त्वचा को लंबे समय तक जवान बनाए रखता है।
- गेंदे के फूल में कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो अल्सर और घाव को ठीक करने में मददगार होते हैं।
- गेंदे के फूल का इस्तेमाल इत्र बनाने में भी किया जाता है।

अनाज से बन सकता है ईंधन

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट के शोधकर्ताओं ने ऐसी सस्ती तकनीक विकसित करने में सफलता हासिल की है, जिसकी सहायता से ब्रेवरीज में बचे जौ को कार्बन में बदल सकते हैं। इसे घरों में रिन्यूएबल फ्यूल के रूप में उपयोग किया जा सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तकनीक की सहायता से वेस्ट को चारकोल में बदल सकते हैं जिससे विकासशील देशों की खाना पकाने और पानी को साफ करने सम्बन्धी चा-रकोल की जरूरत पूरी हो सकती है। इसके संदर्भ में एक विस्तृत शोध जर्नल ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में प्रकाशित हुआ है। गौरतलब है कि हर साल यूरोपियन यूनियन द्वारा ब्रेवरीज में बचा लगभग 34 लाख टन अनाज फेंक दिया जाता है जिसका वजन लगभग 500,000 हाथियों के बराबर होता है।

शिफ्ट में काम करने वालों के लिये खतरे की घंटी

आधुनिक युग में जरूरतों और ज्यादा पैसों के लिये नौकरी या व्यावसाय के चक्कर में आदमी अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। भारत में मधुमेह इसी का नतीता है। शिफ्ट में काम करना भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है

एजेंसियां: कई निजी कंपनियों में चौबीसों घंटे काम होता है। टार्गेट पूरा करने के लिए भी कई कंपनियां अब 24 घंटे काम करने पर जोर दे रही हैं। 24 घंटे ऑफिस चलने का मतलब शिफ्ट में काम करना। सुबह, शाम और रात की शिफ्ट में बड़ी संख्या में एंप्लॉयी काम करते हैं। ज्यादातर ऑफिस में ये शिफ्ट हर हफ्ते बदलती है। पर क्या आप जानते हैं कि हर हफ्ते शिफ्ट में होने वाला बदलाव आपकी बॉडी पर क्या बुरा असर डालता है?

सेहत के लिए खतरा

कभी सुबह, कभी शाम तो कभी रात। अगर आप भी इस तरह की शिफ्ट में काम करते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इससे न सिर्फ मोटापा बल्कि डायबिटीज और कई तरह की दिमागी बीमारियां भी हो सकती हैं। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी में की गई एक स्टडी में इस बात की जानकारी सामने आई है। ये स्टडी 438 लोगों पर की गई थी। शोधकर्ताओं ने बताया कि शिफ्ट में काम करने वालों में 33 फीसदी ज्यादा तनाव और डिप्रेशन पाया गया। वहीं 9 से 5 बजे वाली शिफ्ट में काम करने वालों या एक फिक्स शिफ्ट में काम करने वालों में बहुत कम तनाव पाया गया।

मानसिक बीमारियों का खतरा

शिफ्ट में काम करने वाले लोगों में कई तरह की दिमागी बीमारियां भी हो जाती हैं। स्टडी के मुताबिक 438 लोगों में से 28 फीसदी लोग ऐसे थे जो बदलती शिफ्ट में काम करते थे और वो मानसिक बीमारी से पीड़ित थे। स्टडी करने वाले विशेषज्ञों का कहना है कि बार-बार शिफ्ट में बदलाव होने से लोगों की सोने और जागने की आदत पर असर पड़ता है। हर हफ्ते होने वाले बदलाव को हमारा शरीर जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता जिससे लोग चिड़चिड़े होने लगते हैं।

कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर का खतरा

जापान में हुए एक शोध में ये बात सामने आई कि ऐसे लोग जो शिफ्ट में काम करते हैं उन्हें मोटापा और पाचन संबंधी समस्याएं भी होने लगती हैं। इसके अलावा लोगों में हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल जैसी दिक्कतें भी हो जाती हैं।

दिल्ली में आंख के मरीजों की संख्या बढी

वायु प्रदूषण में हुए इजाफे के साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों में अधिकतर सांस की तकलीफ और आंखों की समस्याओं से घिरे लोग शामिल हैं। हवा की गति में कमी के कारण दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) तेजी से बिगड़ गया।श्री बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट में सीनियर कंसल्टेंट अरविंद अग्रवाल ने बताया, कि दिल्ली में स्मॉग खासकर बच्चों में बहुत सारी चिकित्सा समस्याएं लेकर आता है। हमारे अस्पताल में सांस और आंखों की समस्याओं वाले लोगों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। अग्रवाल ने कहा, "हमने ओपीडी में 20-22 फीसदी की वृद्धि देखी है, जहां मरीजों को आंखों और गले में जलन, शुष्क त्वचा, त्वचा की एलर्जी, पुरानी खांसी और सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षणों का सामना करना पड़ रहा है।

E ZONE CARE

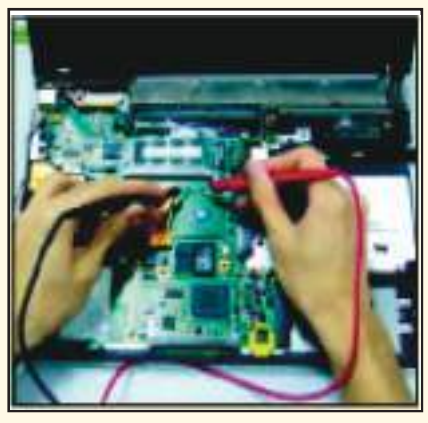

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- Repair your laptop with 3-month warranty.

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, ranchi
93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SunDAY Closed

ध्वनि प्रदूषण से जीव जंतुओं पर अस्तित्व संकट

एजेंसियां: हमारी ज्यादतर चिंता वायु जल और स्थल प्रदूषण पर होती है, ध्वनि प्रदूषण के नुकसानों पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, पर ध्वनि प्रदूषण सिर्फ शोर नहीं बल्कि उससे भी खतरनाक है।

क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट के शोधकर्ताओं के अनुसार मानव द्वारा किया जा रहा ध्वनि प्रदूषण जीवों की 100 से भी अधिक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा है। यह तो सभी जानते हैं कि हमारे द्वारा किया जा रहा शोर हमारे लिए एक बड़ी आफत का सबब बनता जा रहा है। पर क्वीन्स यूनिवर्सिटी, बेलफास्ट के शोधकर्ताओं द्वारा किये गए अध्ययन के अनुसार इसके चलते अनेकों जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। शोधकर्ताओं के अनुसार ध्वनि प्रदूषण सभी तरह के जीवों जैसे पक्षियों, मछलियों, उभयचरों, स्तनधारियों और सरीसृपों सहित सभी प्रजातियों के व्यवहार को बदल रहा है।

यह शोध रॉयल सोसाइटी के जर्नल बायोलॉजी लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। क्वींस यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेज से जुड़े और इस अध्ययन के प्रमुख लेखक डॉ हंसजोर्ग कुन्क के अनुसार यह अध्ययन स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि ध्वनि प्रदूषण प्रजातियों के सभी सातों समूहों को

प्रभावित करता है। प्रजातियों में भिन्नता होने के बावजूद शोर के प्रति उनकी प्रतिक्रिया में अंतर नहीं था।

कीटों से लेकर विशाल व्हेल्स तक नहीं है सुरक्षित

आज मानव जल, थल और नभ हर जगह को अपने शोर से प्रदूषित कर रहा है। चाहे जमीन पर वाहनों से होने वाले शोर को देख लीजिये या उद्योगों की कर्कश ध्वनि को या फिर आसमान में उड़ने वाले जहाज को या फिर पाने में चलने वाले जहाजों को जिसके प्रोपेलर से होने वाले शोर से व्हेल्स पर पड़ने वाले असर को ही देख लीजिये। जिससे उनके सोनार पर असर पड़ रहा है और वे बड़े पैमाने पर अपने पथ से भटक रही है। और मौत के मुंह में जा रही हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार शोर का असर केवल उन प्रजातियों पर ही नहीं पड़ रहा जो धवनि के प्रति संवेदी हैं, बल्कि इसका असर ज्यादातर प्रजातियों पर देखा गया है। डॉ कुन्क ने बताया कि इन सब में दिलचस्प बात यह रही की शोर का असर छोटे कीटों से लेकर व्हेल्स जैसे विशाल जीवों पर पड़ रहा है। शोध के अनुसार यह जरुरी नहीं कि जीवों पर इसका सीधा असर हो। और यह कहना भी आसान नहीं है कि प्रभाव सकारात्मक है या नकारात्मक, पर यह स्पष्ट की उनपर प्रभाव पड़ रहा है और यह उनके अस्तित्व से लेकर आबादी तक को प्रभावित कर रहा है। पक्षी, कीड़े और स्तनधारियों जैसी कई प्रजातियां ध्वनि संकेतों के माध्यम से बात करती हैं। ऐसा वह अपने साथी के चयन से लेकर एक दूसरे को आने वाले खतरे से अवगत कराने में करती हैं। पर यदि ध्वनि प्रदूषण से वह इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा नहीं कर पाएंगी तो यह उनके अस्तित्व को खतरे में डाल देगा । जहां ध्वनि प्रदूषण के चलते कुछ जीव अपने शिकारियों से नहीं बच पर रहे । वहीं इसके विपरीत यह कुछ जीवों के लिए अपना शिकार खोजना मुश्किल कर रहा है। उदाहरण के लिए चमगादड़ और उल्लू को ही ले लीजिये, उनके जैसे जीव संभावित शिकार को उनकी आवाज से पहचानते हैं। पर ध्वनि प्रदूषण उस आवाज को सुनने में दिक्कत पैदा कर रहा है और इसलिए उन्हें अपना शिकार खोजने और भोजन जुटाने में अधिक समय लग रहा है, जिससे इन प्रजातियों में गिरावट आ सकती है। जलीय दुनिया में मछली के लार्वा अपना घर रीफ्स द्वारा उत्सर्जित होने वाली ध्वनि की मदद से ढूंढ़ते हैं। समुद्र में जहाजों के कारण होने वाला ध्वनि प्रदूषण, लार्वा के लिए उपयुक्त घर ढूंढने में कठिनाई पैदा कर रहा है, जिससे अनुपयुक्त रीफ्स के चुनाव के कारण उनका जीवनकाल घट सकता है। शोधकर्ताओं ने पाया कि ध्वनि प्रदूषण के कारण जानवरों के प्रवास पर भी व्यापक असर पड़ रहा है। कई पक्षी प्रवास के दौरान ध्वनि प्रदूषित क्षेत्रों में जाने से बचते हैं। इसके कारण अपने बच्चों को पालने के लिए यह पक्षी कम प्रदूषित क्षेत्रों की ओर प्रवास कर रहे हैं और वहां अपने बसेरे का निर्माण कर रहे हैं । इस तरह के प्रवास के कारण प्रजातियों के वितरण में असमानता आ रही है।

यह परिवर्तन पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हानिकारक हो सकता है क्योंकि प्रत्येक प्रजाति एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। निष्कर्ष के रूप में डॉ कुन्क ने बताया कि "यह अध्ययन इस बात के पक्के सबूत देता है कि मानव द्वारा किये जा रहे ध्वनि प्रदूषण से पर्यावरण में व्यापक परिवर्तन आ रहा है यह प्रदूषण का एक गंभीर रूप है, जिसे वैश्विक स्तर पर देखा जाना चाहिए । अध्ययन से यह भी पता चलता है कि ध्वनि प्रदूषण किस तरह जलीय और स्थलीय प्रजातियों को प्रभावित कर रहा है। आज वैश्विक स्तर पर इसपर गंभीरता से विचार करने की जरुरत है।

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक मनोरंजन सिंह द्वारा प्रकाशित तथा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित और सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2, टीवीएस गली, रातू रोड, रांची-834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094,** email:greenrevolt2019@gmail.com. Ph. 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।